

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0) (सं0 पटना 865) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना 19 अगस्त 2016

सं० 22 नि0 सि0 (दर0)—16—01/2011/1777—श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई कितपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य अभियन्ता, दरभंगा द्वारा श्री कुमार के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र—''क'' विभाग में समर्पित किया गया। उक्त आरोप पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 168 दिनांक 14.02.11 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असतोषजनक पाते हुए इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। फलतः विभागीय सकल्प सह पठित ज्ञापांक 567 दिनांक 30.05.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाहीं संचालन के कालक्रम में श्री कुमार दिनांक 31.05.12 को सेवानिवृत हो गये। माममले के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बीo) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। फलतः अधिसूचना सं0—932 दिनांक 23.08.12 द्वारा श्री कुमार के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बीo) में सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। फलतः विभागीय पत्रांक 1099 दिनांक 13.05.15 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के अन्तर्गत किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही उसी परिस्थिति में चलाई जा सकती है जब कर्मी ने अपने पदस्थापन काल के दौरान सरकार को गंभीर क्षिति पहुँचाई हो अथवा वह ग्रेव मिस्कन्डक्ट का दोषी रहा हो। प्रपत्र—"क" में गठित आरोप न तो वित्तीय क्षित से संबंधित है और न ही ग्रेव मिस्कन्डक्ट से। प्रपत्र—"क" में जो आरोप गठित किया गया है उसे संचालन पदाधिकारी ने अप्रमाणित माना है।

ऐसी स्थिति में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव को स्वीकार करते हुए श्री कुमार को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री कुमारको संसूचित किया जाता है |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 865-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in